[2023] 6 एस.सी.आर. 572

के.सी सिनेमा (सही नाम के.सी थिएटर)

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 77/2023)

03 जनवरी, 2023

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई और
पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226, 19(1)(जी) - जनहित याचिका इस शिकायत के साथ दायर की गई थी कि जम्मू-कश्मीर में सिनेमा थिएटर फिल्म देखने वालों को सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजें लाने से रोक रहे हैं - उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर राज्य के मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल मालिकों को निर्देश दिया कि वे सिनेमा देखने वालों/दर्शकों को थिएटर के अंदर अपनी खाने की चीजें और पानी ले जाने से न रोकें - वैधता - माना गया: सिनेमा थिएटरों के संचालन का व्यापार और व्यवसाय राज्य द्वारा विनियमन के अधीन है - वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने उद्योग को विनियमित करने के लिए 1975 के नियम बनाए थे - इस संबंध में 1975 के नियमों (या किसी अन्य लागू कानून) में एक विशिष्ट शासनादेश की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय को एक फिल्म देखने के लिए मूवी थिएटर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा खाद्य और पेय पदार्थ लाने की अनुमति नहीं देने से थिएटर मालिकों को रोकने का निर्देश जारी करने में न्यायोचित नहीं था - सार्वजनिक हित, सुरक्षा और कल्याण के लिए - मूवी हॉल के परिसर में बाहर से खाद्य और पेय पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध सार्वजनिक हित, सुरक्षा या कल्याण के विपरीत नहीं है - इसके अलावा, कोई फिल्म देखना है या नहीं, यह पूरी तरह से दर्शकों की पसंद के भीतर है - यदि दर्शक किसी सिनेमा हॉल में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें उन नियमों और शर्तों का पालन करना होगा जिनके अधीन प्रवेश दिया जाता है - प्रवेश की शर्त सिनेमा मालिकों के व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार के प्रयोग के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत लगाई गई है - उच्च न्यायालय ने आरोपित निर्देश जारी करके अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया - उक्त निर्देश के संबंध में आरोपित निर्णय को रद्द किया गया - जम्मू और कश्मीर सिनेमा (विनियमन) नियम 1975 - सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 - सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम 1983 - जम्मू और कश्मीर सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1989 - जम्मू और कश्मीर सिनेमैटोग्राफ नियम 1989

अनुबंध - कॉन्ट्रैक्ट - गलत और बेमतलब कॉन्ट्रैक्ट/कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज़ - सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में बताया गया टेस्ट। केस - माना गया: जब एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी के मुकाबले बराबर बारगेनिंग पावर नहीं होती, तो कोई भी नियम और शर्तें जो गलत हों, उन्हें कम बारगेनिंग पावर वाली पार्टी के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता - सेंट्रल इनलैंड ने माना कि क्या पार्टियों के पास बराबर बारगेनिंग पावर नहीं है और क्या कोई बारगेन गलत या गलत है, यह हर केस के फैक्ट्स और हालात के आधार पर तय किया जाना चाहिए - सेंट्रल इनलैंड में टेस्ट सिर्फ यह देखने के लिए नहीं है कि क्या पार्टियों के पास एक-दूसरे के मुकाबले बराबर बारगेनिंग पावर नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाना है कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट की शर्त या कॉन्ट्रैक्ट गलत, गलत या अनुचित है - एक कॉन्ट्रैक्ट (या कॉन्ट्रैक्ट की कोई शर्त) गलत या अनुचित कहा जा सकता है अगर वह एकतरफा हो या उसमें कोई कमर्शियल लॉजिक न हो - हालांकि, इस मामले में, हालांकि थिएटर मालिक सिनेमा हॉल में एंट्री की शर्तें एकतरफा तय कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में लगाई गई शर्त गलत, गलत या अनुचित नहीं है - जम्मू और कश्मीर सिनेमा (विनियमन) नियम 1975

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1 सिनेमा थिएटर चलाने का ट्रेड और बिज़नेस राज्य के रेगुलेशन के तहत आता है। इस मामले में, राज्य सरकार ने इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 1975 के नियम बनाए हैं। माना कि 1975 के नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है जो सिनेमा थिएटर के मालिक को मूवी देखने वालों को थिएटर के अंदर बाहर से खाने-पीने की चीज़ें लाने की इजाज़त देने के लिए मजबूर करे। इसी तरह, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाले दूसरे कानून और नियम, जैसे सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम 1983, जम्मू-कश्मीर सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1989, और जम्मू-कश्मीर सिनेमैटोग्राफ नियम 1989 में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत थिएटर मालिकों को मूवी देखने वालों को सिनेमा हॉल में अपनी खाने-पीने की चीज़ें ले जाने की इजाज़त देनी पड़े। राज्य की नियम बनाने की शक्ति का इस्तेमाल सिनेमा हॉल मालिक के संविधान के आर्टिकल 19(1)(जी) के तहत कानूनी काम, ट्रेड या बिज़नेस करने के बुनियादी अधिकार के हिसाब से किया जाना चाहिए। सिनेमा मालिक को बाहर से खाने-पीने की चीज़ें लाने की इजाज़त देने वाले नियम को कानून बनाने वाली सरकार ने नहीं माना, यह बहुत ज़रूरी है। 1975 के नियमों (या किसी दूसरे लागू कानून) में इस बारे में कोई खास आदेश न होने की वजह से, हाई कोर्ट का यह निर्देश देना सही नहीं था कि थिएटर मालिकों को उन लोगों को खाने-पीने की चीज़ें लाने से रोका जाए जो मूवी

थिएटर में फ़िल्म देखने के लिए आते हैं। हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने रिट अधिकार का इस्तेमाल करने में गलती की है। उसके अधिकार का इस्तेमाल मूवी थिएटर को रेगुलेट करने वाले कानूनों के नियमों के मुताबिक नहीं था। [पैरा 20, 22][583-जी-एच; 584-ए-सी, एफ-जी]

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया **(1997) 5 एससीसी 536: [1996] 10 अनुपूरक एससीआर 585 - अनुसरण किया गया।**

1.2 सिनेमा हॉल, हॉल के मालिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हॉल का मालिक टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने का हकदार है, जब तक कि वे पब्लिक इंटरेस्ट, सेफ्टी और वेलफेयर के खिलाफ न हों। किसी भी दूसरे बिज़नेस की तरह, मालिक या मैनेजमेंट को यह तय करने का हक है कि किस बिज़नेस मॉडल को फॉलो किया जाए और किसी खास बिज़नेस मॉडल के इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में अपने आइडिया को लागू करने का हक है। सिनेमा हॉल का मालिक यह तय करने का हकदार है कि वह खाने-पीने की चीज़ों की बिक्री के लिए काउंटर लगाएगा या किसी एंटिटी को हायर करेगा और उन शर्तों को रेगुलेट करेगा जिन पर ऐसी बिक्री होनी चाहिए। मूवी हॉल के एरिया में बाहर से खाने-पीने की चीज़ें ले जाने पर रोक पब्लिक इंटरेस्ट, सेफ्टी या वेलफेयर के खिलाफ नहीं है। एक मूवी हॉल सिर्फ एक मूवी हॉल नहीं है, बल्कि जब उसके अंदर खाने-पीने की चीज़ें बेची जाती हैं तो वह एक ईटरी का भी काम करता है। जब सिनेमा हॉल के मालिक इसके उलटी शर्त लागू करते हैं तो मूवी हॉल के कस्टमर वहां खाने के लिए अपना खाना लाने की मांग नहीं कर सकते। यह किसी रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर को अपना खाना उस रेस्टोरेंट में ले जाने और रेस्टोरेंट के अंदर खाने की इजाज़त देने जैसा होगा। [पैरा 23, 24][584-जी-एच; 585-ए-ई]

1.3 सिनेमा हॉल में एंट्री मिलने के बाद खाना या ड्रिंक्स खरीदना है या नहीं, यह पूरी तरह से मूवी देखने वाले की मर्ज़ी पर है। दर्शक मनोरंजन के मकसद से सिनेमा हॉल जाते हैं। टिकट खरीदने का ट्रांज़ैक्शन उन्हें वह मूवी देखने की इजाज़त देता है जिसे उन्होंने देखना चुना है। अगर मूवी हॉल में बिकने वाला खाना और ड्रिंक्स उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो वे उन्हें खरीदने से मना कर सकते हैं। इस तरह, उन्हें खाना चुनने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा रहा है। मूवी देखना है या नहीं, यह पूरी तरह से दर्शकों की मर्ज़ी पर है।

अगर दर्शक सिनेमा हॉल में घुसना चाहते हैं, तो उन्हें उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना होगा जिनके तहत एंट्री दी जाती है। एंट्री का अधिकार रिज़र्व रखने के बाद, यह थिएटर मालिकों पर निर्भर है कि वे यह तय करें कि सिनेमा हॉल के बाहर से खाना अंदर ले जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं। उच्च न्यायालय ने सिनेमा हॉल मालिकों को यह निर्देश देकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया कि वे फिल्म देखने वालों को सिनेमा हॉल के परिसर में बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने से न रोकें और राज्य को सिनेमा हॉल मालिकों पर यह निर्देश लागू करने का निर्देश दें। सिनेमा हॉल संचालन का व्यवसाय करने के अधिकार को विनियमित करने वाले वैधानिक विनियमन के अभाव में, इस तरह का प्रतिबंध लगाने से थिएटर मालिक के वैध अधिकार प्रभावित होंगे। प्रवेश की शर्त संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत सिनेमा मालिकों द्वारा व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार के प्रयोग के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में लगाई गई है। फिल्म देखने वालों को सिनेमा हॉल में अपना खाना ले जाने से रोकने का व्यावसायिक तर्क व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण पहलू - खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना है। 587-जी-एच]

1.4 पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मूवी देखने वालों के लिए, जिन्हें शायद उनके डॉक्टरों ने खाने-पीने की सलाह दी हो या जो अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से खाने-पीने की पाबंदियों में हों, सिनेमा हॉल मालिकों से रिक्वेस्ट है कि वे ऐसे मूवी देखने वालों की रिक्वेस्ट पर केस-बाई-केस बेसिस पर विचार करें। [पैरा 34][588-जी]

1.5 निर्देश (i) के संबंध में हाई कोर्ट का विवादित फैसला और आदेश रद्द किया जाता है। [पैरा 35][588-एच]

1.6 पार्कर बनाम द साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी **(1877) 2 सी.डी.पी 416;** ओली बनाम मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड **(1949) 1 के.बी 523;** मैककचेन बनाम डेविड मैकब्रेन लिमिटेड **(1964) 1 डब्लू.एल.आर 125;** थॉर्नटन बनाम शू लेन पार्किंग लिमिटेड **(1970) ई.डब्लू.सी.ए सीआईवी 2 - विशिष्ट।**

सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली, **(1986) 3 एससीसी 156: [1986] 2 एससीआर 278 - पर भरोसा किया गया।**

अलगापुरम आर. मोहनराज बनाम टी.एन. विधान सभा, **(2016) 6 एस.सी.सी 82 : [2016] 6 एस.सी.आर 611;** आई.आर.ई.ओ ग्रेस रियलटेक (पी) लिमिटेड बनाम अभिषेक खन्ना, **(2021) 3 एस.सी.सी 241**; जैकब पुन्नन बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, **(2022) 3 एस.सी.सी 655 - को संदर्भित किया गया।**

केस लॉ संदर्भ

[2016] 6 एससीआर 611	**संदर्भ**	**पैरा 19**
[1996] 10 अनुपूरक एस.सी.आर. 585	**अनुसरणित**	**पैरा 21**
[1986] 2 एससीआर 278	**भरोसा किया गया**	**पैरा 29**

सिविल अपील/मूल क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 77/2023.

दिनांक 18.07.2018 जनहित याचिका संख्या 11/2018 जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू के निर्णय और आदेश से

साथ ही

सिविल अपील संख्या 78 और 79/2023, स्थानांतरित मामला संख्या 28 और 29/2019

के.वी. विश्वनाथन, निरंजन रेड्डी, बिमल रॉय जाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव श्रीवास्तव, राहुल गुप्ता, आर.पी. सिंह, शिवांग रावत, सुश्री राधिका जालान, सुमीर सोढ़ी, अर्जुन नंदा, साहिल नारंग, धृतिमान रॉय, माधवम शर्मा, आयुष्मान कक्कड़, सुश्री सानिया अब्बासी, अखिला, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, शिवम शर्मा, दिवस कुमार, सुश्री ट्विंकल, राज किशोर चौधरी, मुनव्वर नसीम, आदित्य शर्मा, डॉ. नीलाक्षी चौधरी, अतुल महान, सुश्री पूर्णिमा जौहरी, सुश्री तरुणा अर्धेंदुमौली प्रसाद, श्रीमती मृणाल एलकर मजूमदार, शैलेश मडियाल, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार, विनायक. एस. पंडित, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सुश्री कीर्ति दाधीच, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय के प्रस्ताव द्वारा
कोर्ट ने निम्नलिखित फैसला सुनाया:

विषयसूची*

ए. बैकग्राउंड..... 3
बी. रेस्पोंडेंट्स द्वारा जिन केस पर दृष्टांत किया गया.....7
सी. हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत
अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है.....11
डी. आखिरी टिप्पणी..... 19

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सी.जे.आई

<u>सिविल अपील संख्या - 77, 78 और 79/2023</u>

1. अनुमति प्रदान की गयी।

ए. बैकग्राउंड

2. अपीलों का यह बैच जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच के 18 जुलाई 2018 के एक फ़ैसले से जुड़ा है। दो प्रैक्टिसिंग वकीलों ने हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की थी, जिसमें शिकायत थी कि जम्मू और कश्मीर के सिनेमा थिएटर मूवी देखने वालों को सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीज़ें लाने से रोक रहे हैं। इस मामले में, यह कहा गया कि सिनेमा मालिक हॉल के बाहर एक नोटिस चिपकाते हैं जिसमें इस रोक के बारे में बताया गया है और सिक्योरिटी वाले हर सिनेमा देखने वाले के सामान की तलाशी लेते हैं ताकि रोक लागू हो सके। अगर मूवी देखने वालों के पास खाने-पीने की चीज़ें पाई जाती हैं, तो उन्हें (कहा गया) सिनेमा हॉल में अंदर जाने से रोका जाता है।

3. हाई कोर्ट के सामने यह दलील दी गई थी कि रोक की वजह से, मूवी देखने वालों को सिनेमा हॉल के अंदर मिलने वाला खाना और ड्रिंक्स लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे दर्शकों को "बहुत ज़्यादा रेट" पर खाना खरीदना पड़ता है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि जो खाना बेचा जाता है, वह ज़रूरी नहीं कि पौष्टिक हो और जिन लोगों को पुरानी बीमारियाँ (जैसे डायबिटीज़) हैं, उन्हें एक खास तरह का खाना खाना पड़ सकता है जो मूवी हॉल में नहीं मिलेगा।

4. हाई कोर्ट को पैरा 6 में दिए गए अपने नतीजों के आधार पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में राहत देने के लिए मना लिया गया, जो नीचे दिया गया है:

> **"6.** इन नियमों को देखने से पता चलता है कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सिनेमा देखने वालों को मल्टीप्लेक्स में अपना खाने का सामान और पानी की बोतलें ले जाने से रोका जा सकता है या प्राइवेट वेंडर को ऐसे मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल परिसर में बहुत ज़्यादा दामों पर खाना बेचने की इजाज़त है। इसलिए, ऐसे किसी भी नियम के न होने पर, सिनेमा देखने वालों को मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल मालिक थिएटर परिसर से खाना और पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और न ही उन्हें बाहर से मॉल और मल्टीप्लेक्स में खाने का सामान ले जाने से रोका जा सकता है। यहां तक कि जो दर्शक अपने छोटे बच्चों के साथ आते हैं, उन्हें भी दूध की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें लगभग तीन घंटे तक खाली पेट नहीं रखा जा सकता। थिएटर में बाहर का खाना लाने पर रोक और थिएटर परिसर के अंदर खाने के स्टॉल पर बिकने वाला जंक फ़ूड, वह भी बहुत ज़्यादा दामों पर, खरीदने के लिए मजबूर करना/मजबूर करना, खासकर युवा पीढ़ी, बुज़ुर्गों, डायबिटीज़ के मरीज़ों और उन लोगों पर असर डालता है जो मेडिकल कारणों से खाना नहीं खा सकते। मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल मालिकों की इस तरह की हरकतें खाने की पसंद के अधिकार के खिलाफ हैं, जिसमें जंक फ़ूड न खाने का अधिकार भी शामिल है और अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है।"

5. हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर सिनेमा (रेगुलेशन) रूल्स 1975[1] को नोटिफाई किया था। हाई कोर्ट ने कहा कि:

I. 1975 के नियम सिनेमा जाने वालों को मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल में अपने खाद्य पदार्थ और पानी की बोतलें ले जाने से नहीं रोकते हैं;

II. सिनेमा हॉल मालिकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, दर्शकों को उस प्रकृति का खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जो थिएटर के परिसर में बिक्री के लिए पेश किया जाता है;

III. जिन शिशुओं को समय-समय पर भोजन कराने की आवश्यकता होती है, उन्हें साथ आए माता-पिता या अभिभावकों द्वारा भोजन नहीं दिया जा सकता है;

IV. दर्शकों को थिएटर के अंदर फ़ूड स्टॉल से "जंक" फ़ूड खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और खरीदे गए खाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसका असर खास तौर पर युवा पीढ़ी, बुज़ुर्गों, डायबिटीज़ के मरीज़ों और उन लोगों पर पड़ता है जो मेडिकल वजहों से थिएटर के अंदर बिकने वाला खाना नहीं खा पाते हैं; और

V. मूवी थिएटर में बाहर से खाने-पीने की चीज़ें ले जाने पर रोक, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले खाने के अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें "जंक" फ़ूड न खाने का अधिकार और अच्छी सेहत का अधिकार भी शामिल है।

6. हाई कोर्ट ने शिकायतों को स्वीकार करते हुए, विवादित फैसले और ऑर्डर में कई निर्देश जारी किए। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती निर्देश (i) तक ही सीमित है, जिसे नीचे दिया गया है:

i. जम्मू-कश्मीर राज्य के मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि वे सिनेमा जाने वालों/दर्शकों को अब से थिएटर के अंदर अपना खाने का सामान और पानी ले जाने से न रोकें।"

7. अपील करने वालों की ओर से सीनियर वकील श्री के वी विश्वनाथन, सीनियर वकील श्री निरंजन रेड्डी और श्री सुमीर सोढ़ी के साथ पेश हुए, उन्होंने कहा कि:

i. सिनेमा हॉल का परिसर निजी संपत्ति होता है, जिसमें प्रवेश थियेटर के मालिक द्वारा आरक्षित रखा जाता है;

ii. राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए 1975 के नियम में यह प्रावधान नहीं है कि फिल्म देखने वालों को सिनेमा हॉल के परिसर में बाहर से खाने-पीने की चीजें लाने की अनुमति दी जाएगी;

iii. एक बार फिल्म देखने के लिए टिकट खरीद लेने के बाद किसी भी व्यक्ति पर थिएटर जाने या थिएटर के परिसर में खाना खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है;

iv. जहां तक पीने के पानी की बिक्री का सवाल है, सिनेमा हॉल यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं कि फिल्म देखने वालों के लिए मूवी थिएटर

के परिसर में स्वच्छ पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें पैकेज्ड पेयजल के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर न किया जाए;

v. आम तौर पर, हॉल के बाहर से खाना या ड्रिंक्स लाने पर रोक छोटे बच्चों के मामले में लागू नहीं होती है, उनके माता-पिता या उनके साथ आने वाले गार्जियन को थिएटर में उनके आने के समय के लिए ज़रूरी खाना या ड्रिंक्स लाने की इजाज़त होती है; और

vi. सिविल अपील नंबर 78/2023 में अपील करने वाले थिएटर ने मूवी देखने वालों को जो सिनेमा टिकट दिए हैं, उनमें यह लिखा है कि बाहर से खाने-पीने की चीज़ें और बोतलें (खाली या भरी हुई) सिनेमा हॉल के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। टिकट में यह भी लिखा है कि सिनेमा हॉल में एंट्री का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8. दूसरी ओर, हाई कोर्ट में ओरिजिनल पिटीशनर्स (इस कार्रवाई में उत्तरदाता नंबर 3 और 4) की ओर से पेश हुए सीनियर अधिवक्ता श्री बिमल रॉय जाद ने कहा कि:

i. सिनेमा हॉल द्वारा जारी किया गया सिनेमा टिकट फिल्म देखने वाले के साथ एक अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है और टिकट की मुद्रित शर्तों पर किसी भी निषेध के अभाव में, फिल्म देखने वाले को थिएटर के अंदर खाने-पीने की चीजें लाने से नहीं रोका जा सकता है;

ii. सिनेमा हॉल की रोक की वजह से, मूवी देखने वालों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि उन्हें मूवी हॉल के अंदर खाने-पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा दाम पर खरीदनी पड़ती हैं; और

iii. 1975 के नियमों में सिनेमा हॉल के अंदर बाहर से खाने-पीने की चीज़ें लाने पर कोई रोक नहीं है।

बी. उत्तरदाताओं द्वारा दृष्टांत किए गए मामले

9. प्र उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने विवादित फैसले में दिए गए निर्देशों के समर्थन में नीचे दिए गए फैसलों का सहारा लिया है:

i. **पार्कर** बनाम **दक्षिण पूर्वी रेलवे कंपनी** (1877) 2 सी.डी.पी 416;

ii. **ओली** बनाम **मार्लबोरो कोर्ट लिमिटेड** (1949) 1 के.बी 523;

iii. **मैककचेन** बनाम **डेविड मैकब्रेन लिमिटेड** (1964) 1 डब्लू.एल.आर 125; और

iv. **थॉर्नटन** बनाम **शू लेन पार्किंग लिमिटेड** (1970) ई.डब्ल्यू.सी.ए सिविल 2

10. यह समझने के लिए कि क्या इन फैसलों के फैसले हमारे सामने मौजूद केस पर लागू होते हैं, यह जानना ज़रूरी है कि वे किस कॉन्टेक्स्ट में आए, कोर्ट के तय किए गए कानूनी सवाल क्या थे, और उनमें क्या राहत मिली।

11. **पार्कर** के केस (उपरोक्त) में, वादी ने अपना कुछ सामान रेलवे स्टेशन के क्लोकरूम में जमा किया था। सामान जमा करते समय, उसे एक टिकट मिला जिस पर "पीछे देखें" लिखा था। टिकट के पीछे लिखा था, "कंपनी 10। से ज़्यादा कीमत के किसी भी पैकेज के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।" दीवार पर भी इसी शर्त वाला एक प्लेकार्ड लटका हुआ था। वादी का सामान खो गया था या चोरी हो गया था और उसने खोए हुए सामान की कीमत के लिए डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया। वादी ने जमा किए गए किसी भी सामान के लिए डिफेंडेंट की ज़िम्मेदारी के बारे में टिकट या दीवार पर लगे प्लेकार्ड पर शर्त नहीं देखी थी। उस मामले में कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या वादी के सामान के नुकसान के लिए रेस्पोंडेंट ज़िम्मेदार था।

12. **ओली** के केस (उपरोक्त) में, वादी डिफेंडेंट के होटल में पेइंग गेस्ट थी। कमरे का पेमेंट करने के बाद, उसे अपनी चाबियां मिलीं और वह अपने कमरे में चली गई। वहां, कई टर्म्स एंड कंडीशंस वाला एक नोटिस लगा था। उनमें से एक कंडीशंस यह थीं, "मालिक खोए या चोरी हुए सामान के लिए खुद को ज़िम्मेदार नहीं मानेंगे, जब तक कि उसे मैनेजर को सेफ कस्टडी के लिए न सौंप दिया जाए।" वादी का सामान बाद में उसके कमरे से चोरी हो गया। वादी ने डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया और उससे चुराए गए सामान की कीमत का दावा किया। कोर्ट को यह तय करना था कि क्या डिफेंडेंट कॉमन लॉ के तहत खुद को लायबिलिटी से बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर भरोसा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह तय करने के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या वादी को हुए नुकसान के लिए डिफेंडेंट ज़िम्मेदार था।

13. **मैककचेन** के केस (उपरोक्त) में, वादी ने अपनी कार समुद्र के रास्ते दूसरे शहर में डिलीवर करवाने के लिए एक एजेंट को हायर किया। एजेंट ने डिफेंडेंट को पेमेंट किया, रसीद ली और कार डिलीवर कर दी। कार को जहाज़ पर लोड किया गया जो रवाना हुआ। लेकिन, अपनी मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही, डिफेंडेंट के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वह डूब गई। वादी ने अपनी कार की कीमत के लिए डिफेंडेंट पर केस कर दिया। डिफेंडेंट ने इस आधार पर ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया कि वह आमतौर पर

कस्टमर्स से एक रिस्क नोट पर साइन करने के लिए कहता था, जिसमें कस्टमर्स द्वारा भेजे गए सामान को हुए नुकसान के लिए उसकी ज़िम्मेदारी से जुड़े कुछ नियम और शर्तें होती थीं। इस मामले में वादी के एजेंट ने ऐसे किसी रिस्क नोट पर साइन नहीं किया था, लेकिन उसने पहले भी रिस्क नोट पर साइन किए थे जब उसने डिफेंडेंट की शिपिंग सर्विस का इस्तेमाल किया था। डिफेंडेंट ने तर्क दिया कि वह कार के नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा क्योंकि वादी के एजेंट को एक-दूसरे के साथ अपने लेन-देन के दौरान नियम और शर्तों के बारे में पता था। इस मामले में भी, कोर्ट के सामने यह सवाल आया कि क्या वादी की कार के नुकसान के लिए डिफेंडेंट को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

14. आखिर में, **थॉर्नटन** के केस (ऊपर) में, वादी डिफेंडेंट की ऑटोमैटिक कार पार्किंग में गया। इस सर्विस का फायदा उठाने के चार्ज कार पार्किंग के बाहर दिखाए गए थे। वादी एंट्रेंस तक गया और एक मशीन ने एक टिकट निकाला, जिस पर लिखा था, "यह टिकट जगह पर दिखाई गई शर्तों के तहत जारी किया गया है।" वादी ने अपनी कार कार पार्किंग में पार्क की। जब वह बाद में अपनी कार लेने के लिए वहां लौटा, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। उसने डिफेंडेंट के खिलाफ अपनी चोटों के लिए हर्जाने की मांग करते हुए केस शुरू किया। कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या वादी को लगी चोटों के लिए डिफेंडेंट जिम्मेदार होगा।

15. चारों केस इस बात से जुड़े हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर किसी एक पार्टी पर लायबिलिटी लगाई जा सकती है। हर फैसले में यह बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कब किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या थे। कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या कोई खास टर्म, जिसे किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाने का इरादा किया था, असल में कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनेगी और दूसरी पार्टी को बांधेगी, जिससे पहली पार्टी को हुए नुकसान के लिए लायबिलिटी से छूट मिल जाएगी।

16. हमारे सामने जो केस है, वह उन चार केस से अलग है जिन पर रेस्पोंडेंट्स ने भरोसा किया है। इसमें हाई कोर्ट में ओरिजिनल पिटीशनर्स ने अपने नुकसान या चोट के लिए डैमेज या दूसरी राहत के लिए कोई केस फाइल नहीं किया था। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू की और संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन में नीचे दी गई राहत का दावा किया:

> "(ii) प्रतिवादी संख्या 3 – 6 को सिनेमा हॉल के अंदर बाहर से खाने-पीने की चीजें

ले जाने से फिल्म देखने वालों को रोकने के लिए रिट, जिसे सिनेमा हॉल में फीचर फिल्म देखने के दौरान खाना जरूरी है।"

17. एक रिट याचिका दायर करके, उत्तरदाता 3 और 4 ने इस बात पर फैसला मांगा है कि थिएटर मालिकों द्वारा तय और लागू की गई एंट्री की शर्तें सही और निष्पक्ष हैं या नहीं। इसलिए, इस कोर्ट द्वारा लागू किया जाने वाला टेस्ट यह नहीं बताएगा कि थिएटर मालिकों और फिल्म देखने वालों के बीच कौन सी शर्तें उन पर लागू होती हैं और क्या थिएटर परिसर में बाहर का खाना ले जाने पर रोक एक ज़रूरी शर्त है। इसी तरह, इस कोर्ट को यह तय करने के लिए नहीं कहा गया है कि बाहर के खाने पर रोक लागू होने से उत्तरदाता 3 और 4 को कोई चोट लगी है या नहीं और क्या उन्हें लगी चोट के कारण वे हर्जाने के हकदार हैं। बल्कि, यह कोर्ट यह देखेगा कि क्या यह संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए सही मामला था।

18. अगर उत्तरदाता 3 और 4 का मामला यह था कि मूवी हॉल में खाने-पीने की चीज़ें ले जाने पर रोक की वजह से उन्हें कुछ नुकसान हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें उन्हें सिर्फ़ उसके लागू होने के समय ही बताई गई थीं और उन्होंने टिकट के लिए चुकाई गई रकम का रिफंड मांगा था क्योंकि उन्होंने ऐसी किसी शर्त या हर्जाने के लिए अपनी मंज़ूरी नहीं दी थी, तो सही उपाय केस करना होगा, न कि रिट जारी करने की मांग करना। पार्कर (उपरोक्त), ओली (उपरोक्त), मैककचियन (उपरोक्त), और थॉर्नटन (उपरोक्त) के फ़ैसलों, जिन पर उत्तरदाता भरोसा करते हैं, का इस कोर्ट के सामने मौजूद मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि क्या हाई कोर्ट का संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना सही था। इसलिए, इस कोर्ट के लिए इन मामलों के रेश्यो डिसीडेन्डी पर आगे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है।

सी. हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है

19. संविधान का आर्टिकल 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी प्रोफेशन करने, या कोई भी काम, व्यापार या बिज़नेस करने के अधिकार को मान्यता देता है। इस अधिकार में वे सभी एक्टिविटीज़ शामिल हैं जिनसे नागरिकों को आर्थिक फ़ायदा हो और वे अपना गुज़ारा कर सकें।2 आर्टिकल 19(1)(g) में मान्यता दिया गया अधिकार कोई बिना रोक-टोक वाला अधिकार नहीं है और राज्य आर्टिकल 19(6) के तहत उस अधिकार के इस्तेमाल पर उचित रोक लगा सकता है।

20. सबसे ज़रूरी बात जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, वह यह है कि सिनेमा थिएटर चलाने

का काम और बिज़नेस राज्य के रेगुलेशन के तहत आता है। इस मामले में, राज्य सरकार ने इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 1975 के नियम बनाए हैं। माना कि 1975 के नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है जो सिनेमा थिएटर के मालिक को मूवी देखने वालों को थिएटर के अंदर बाहर से खाने-पीने की चीज़ें लाने की इजाज़त देने के लिए मजबूर करे। इसी तरह, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाले दूसरे कानून और नियम, जैसे कि सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) रूल्स 1983, जम्मू और कश्मीर सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1989, और जम्मू और कश्मीर सिनेमैटोग्राफ रूल्स 1989 में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत थिएटर मालिकों को मूवी देखने वालों को सिनेमा हॉल में अपना खाना-पीना ले जाने की इजाज़त देनी पड़े। राज्य की नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के अर्थ के भीतर वैध व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने के लिए सिनेमा हॉल मालिक के मौलिक अधिकार के अनुरूप किया जाना चाहिए।

21. **मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया**[3] मामले में इस कोर्ट की नौ जजों की बेंच की मेजॉरिटी ओपिनियन जस्टिस जीवन रेड्डी ने लिखी थी, जिन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते समय कानूनी इरादे का ध्यान रखना चाहिए:

> **"108** (i). हालांकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र – और आर्टिकल 32 के तहत इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र – इन कानूनों के नियमों से बंधा नहीं हो सकता, फिर भी वे इन कानूनों के नियमों से साबित कानूनी इरादे का ज़रूर ध्यान रखेंगे और एक्ट के नियमों के हिसाब से अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे... ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत मिली ताकत का इस्तेमाल कानून का राज लागू करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उसे खत्म करने के लिए।"

22. सिनेमा मालिक को बाहर से खाने-पीने की चीज़ें लाने की इजाज़त देने वाले नियम को कानून बनाने वाली सरकार ने नहीं माना, यह बहुत ज़रूरी है। 1975 के नियमों (या किसी दूसरे लागू कानून) में इस बारे में कोई खास आदेश न होने की वजह से, हाई कोर्ट का यह निर्देश देना सही नहीं था कि थिएटर मालिकों को उन लोगों को खाने-पीने की चीज़ें लाने से रोका जाए जो मूवी थिएटर में फ़िल्म देखने के लिए आते हैं। हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने रिट अधिकार का इस्तेमाल करने में गलती की है। उसके अधिकार का इस्तेमाल मूवी थिएटर को रेगुलेट करने वाले कानूनों के नियमों के मुताबिक नहीं था।

23. सिनेमा हॉल, हॉल के मालिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हॉल का मालिक टर्म्स एंड कंडीशंस

तय करने का हकदार है, जब तक कि वे पब्लिक इंटरेस्ट, सेफ्टी और वेलफेयर के खिलाफ न हों। किसी भी दूसरे बिज़नेस की तरह, मालिक या मैनेजमेंट को यह तय करने का हक है कि कौन सा बिज़नेस मॉडल फॉलो किया जाएगा और किसी खास बिज़नेस मॉडल के इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में अपने आइडिया को लागू करने का हक है। सिनेमा हॉल का मालिक यह तय करने का हकदार है कि वह खाने-पीने की चीज़ों की बिक्री के लिए काउंटर लगाएगा या किसी एंटिटी को हायर करेगा और यह तय करेगा कि ऐसी बिक्री किन शर्तों पर होनी चाहिए। मूवी हॉल के अंदर बाहर से खाने-पीने की चीज़ें ले जाने पर रोक पब्लिक इंटरेस्ट, सेफ्टी या वेलफेयर के खिलाफ नहीं है।

24. आजकल, मल्टीप्लेक्स या मूवी हॉल सिर्फ़ ऐसी जगह नहीं हैं जहाँ फ़िल्में दिखाई जाती हैं। मूवी हॉल को ज़्यादा सही तरह से एंटरटेनमेंट सेंटर या एंटरटेनमेंट बंडल के तौर पर बताया जाता है। अलग-अलग तरह के खाने-पीने की चीज़ों की बिक्री सिनेमा हॉल में मिलने वाले एंटरटेनमेंट के पूरे पैकेज का एक हिस्सा होती है। दूसरे शब्दों में, एक मूवी हॉल सिर्फ़ एक मूवी हॉल नहीं है, बल्कि जब उसके अंदर खाने-पीने की चीज़ें बेची जाती हैं, तो वह खाने की जगह का भी काम करता है। इस नज़रिए से देखने पर, यह तुरंत साफ़ हो जाता है कि मूवी हॉल के ग्राहक वहाँ खाने के लिए अपना खाना लाने की माँग नहीं कर सकते, जब सिनेमा हॉल मालिक इसके उलट कोई शर्त लागू करते हैं। यह वैसा ही होगा जैसे किसी रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक को अपना खाना उस रेस्टोरेंट में ले जाने और उसी रेस्टोरेंट के अंदर खाने की इजाज़त देना।

25. उत्तरदाता 3 और 4 ने कहा है कि उन्हें अपना खाना साथ ले जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए क्योंकि सिनेमा हॉल बहुत ज़्यादा कीमत पर खाने-पीने की चीज़ें बेचते हैं, जो पौष्टिक भी नहीं होतीं। हाई कोर्ट को यह निर्देश जारी करने के लिए मनाया गया, जैसा कि पहले बताया गया है, इस आधार पर कि जो बेचा जा रहा है वह "जंक फ़ूड" है। थिएटर मालिक अपने मेन्यू में क्या होगा, यह तय कर सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट अपना मेन्यू तय करते हैं या जैसे थिएटर मालिक खुद तय करते हैं कि कौन सी फ़िल्में दिखानी हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक कमर्शियल फ़ैसला है जिसे थिएटर मालिक लेने के हकदार हैं। सामान और सर्विस जिस कीमत पर बेची जाएंगी, वह भी मूवी थिएटर तय करेगा। किसी सामान या सर्विस की कीमत सस्ती है या बहुत ज़्यादा, इसका किसी बिज़नेस द्वारा लागू की गई एंट्री की शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है।

26. हाई कोर्ट के फैसले में तर्क का दूसरा लेवल यह है कि जिस रोक की बात हो रही है, वह खाने की पसंद के अधिकार, "जंक" फ़ूड न खाने के अधिकार और अच्छी सेहत के अधिकार पर असर डालती है। हालांकि, इस तर्क में यह ध्यान नहीं दिया गया है कि

मूवी देखने वालों को सिनेमा हॉल में खाना खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। सिनेमा हॉल में एंट्री मिलने के बाद खाना या ड्रिंक्स खरीदना है या नहीं, यह पूरी तरह से मूवी देखने वाले की मर्ज़ी पर है। दर्शक मनोरंजन के मकसद से सिनेमा हॉल जाते हैं। टिकट खरीदने का लेन-देन उन्हें वह मूवी देखने की इजाज़त देता है जिसे उन्होंने देखना चुना है। अगर मूवी हॉल में बिकने वाला खाना और ड्रिंक्स उनके टेस्ट का नहीं है, तो वे उन्हें खरीदने से मना कर सकते हैं। इस तरह, उन्हें खाने की पसंद के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा रहा है। हम यह भी देखते हैं कि मूवी देखने वालों का अपनी पसंद की डिश खरीदने या खाने का अधिकार प्राइवेट तौर पर चलाए जाने वाले मूवी थिएटर के दायरे के बाहर भी बिना किसी रोक-टोक के है (सुरक्षा और पब्लिक वेलफेयर के अधीन)।

27. कोई फ़िल्म देखना है या नहीं, यह पूरी तरह से दर्शकों की मर्ज़ी है। अगर दर्शक सिनेमा हॉल में अंदर जाना चाहते हैं, तो उन्हें उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना होगा जिनके तहत एंट्री दी जाती है। एंट्री का अधिकार सुरक्षित रखने के बाद, यह थिएटर मालिकों पर निर्भर है कि वे तय करें कि सिनेमा हॉल के बाहर से खाना अंदर ले जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं।

28. इसलिए हमारा मानना है कि हाई कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उसने सिनेमा हॉल मालिकों को यह निर्देश दिया कि वे सिनेमा हॉल के अंदर बाहर से खाने-पीने की चीज़ें लाने से मूवी देखने वालों पर रोक न लगाएं और राज्य को यह निर्देश सिनेमा हॉल मालिकों पर लागू करने का निर्देश दिया। सिनेमा हॉल चलाने के अधिकार को रेगुलेट करने वाले किसी कानूनी नियम के बिना, ऐसी रोक लगाने से थिएटर मालिक के कानूनी अधिकारों पर असर पड़ेगा।

29. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि सिनेमा मालिकों या दूसरी कमर्शियल कंपनियों के लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस हर मामले में कंज्यूमर या कस्टमर को बांधते हैं। जैसा कि इस कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है, जब एक पार्टी की दूसरी पार्टी के मुकाबले बारगेनिंग पावर बराबर नहीं होती है, तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो गलत हों, उन्हें कम बारगेनिंग पावर[4] वाली पार्टी के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता। सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली[5] में,

इस कोर्ट ने कहा कि क्या पार्टियों के पास बारगेनिंग पावर बराबर नहीं है और क्या कोई बारगेन गलत या गलत है, यह हर मामले के फैक्ट्स और हालात के आधार पर तय किया जाना चाहिए:

> "89. ... यह सिद्धांत यह है कि कोर्ट किसी गलत और तर्कहीन कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट के किसी गलत और तर्कहीन क्लॉज़ को लागू नहीं करेंगे और जब ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो उसे रद्द कर देंगे, जो उन पार्टियों के बीच हुआ हो जिनकी मोलभाव करने की ताकत बराबर नहीं है। इस तरह के सभी मोलभाव की पूरी लिस्ट देना मुश्किल है। ... यह उन स्थितियों पर लागू होगा जिनमें कमज़ोर पार्टी ऐसी स्थिति में हो कि वह सिर्फ़ मज़बूत पार्टी द्वारा लगाई गई शर्तों पर ही सामान या सर्विस या रोज़ी-रोटी का साधन पा सके या उनके बिना रह सके। यह तब भी लागू होगा जब किसी आदमी के पास कोई चॉइस नहीं होती, या यूँ कहें कि कोई मतलब का चॉइस नहीं होती, सिवाय इसके कि वह किसी कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी मंज़ूरी दे या किसी तय या स्टैंडर्ड फ़ॉर्म में डॉटेड लाइन पर साइन करे या कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर नियमों के एक सेट को माने, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट या फ़ॉर्म या नियमों में कोई क्लॉज़ कितना भी गलत, तर्कहीन और बेतुका क्यों न हो। ... ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हो सकती हैं जिनके नतीजे में पूरी तरह से अलग और असमान मोलभाव करने की ताकत रखने वाली पार्टियों के बीच गलत और तर्कहीन मोलभाव होते हैं। इन मामलों को न तो न तो गिना गया है और न ही पूरी तरह से दिखाया गया है। कोर्ट को हर केस को उसके अपने फैक्ट्स और हालात के आधार पर देखना चाहिए।"

30. **सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन** (उपरोक्त) में टेस्ट सिर्फ़ यह देखने के लिए नहीं है कि पार्टियों के पास एक-दूसरे के मुकाबले मोलभाव करने की बराबरी की पावर है या नहीं, बल्कि यह भी पता लगाने के लिए है कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई शर्त या कॉन्ट्रैक्ट गलत, बेमतलब या गलत है या नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट (या कॉन्ट्रैक्ट की कोई शर्त) को गलत या गलत तब कहा जा सकता है जब वह एकतरफ़ा हो या उसमें कोई कमर्शियल लॉजिक न हो। इस मामले में, हालांकि थिएटर मालिक सिनेमा हॉल में एंट्री की शर्तें एकतरफ़ा तय कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में लगाई गई शर्त गलत, बेमतलब या गलत नहीं है।

31. एंट्री की यह शर्त सिनेमा मालिकों के संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के तहत बिज़नेस या ट्रेड करने के अधिकार के सीधे नतीजे के तौर पर लगाई गई है। मूवी देखने वालों को सिनेमा हॉल में अपना खाना ले जाने से रोकने का कमर्शियल लॉजिक बिज़नेस के

एक ज़रूरी हिस्से - खाने-पीने की चीज़ों की बिक्री - को बढ़ावा देना और बढ़ावा देना है। अगर बिज़नेस मालिकों को अपने बिज़नेस के अलग-अलग पहलुओं को (कानून के मुताबिक) तय करने की इजाज़त नहीं है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह रुक जाएगी। जबकि मूवी देखने वालों के पास सिनेमा हॉल में घुसने और अपनी पसंद की मूवी देखने के लिए कहावत वाली डॉटेड लाइन पर साइन करने (और इस तरह थिएटर में अपना कोई खाना न ले जाने) के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, यह अपने आप में एंट्री की शर्त को गलत, बेतुका या गलत नहीं बनाता है।

32. ज़्यादातर बिज़नेस कोई न कोई ऐसी शर्त लगाते हैं जो कस्टमर को ठीक नहीं लग सकती। जैसे, कई प्राइवेट म्यूज़ियम कस्टमर को डिस्प्ले पर रखी चीज़ों की फ़ोटो लेने की इजाज़त नहीं देते। यह बात कई कपड़ों के बुटीक या ज्वेलरी स्टोर के लिए भी सच है। कॉन्सर्ट में म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंस रिकॉर्ड करने पर अक्सर ऑडियंस को बैन कर दिया जाता है। म्यूज़िक फ़ेस्टिवल, मूवी थिएटर की तरह ही, आने वाले लोगों को वेन्यू पर अपना खाना या ड्रिंक्स ले जाने की इजाज़त नहीं देते। ऐसा ही स्टैंड-अप कॉमेडी शो या नाटकों के साथ होता है जो खाने की जगहों या बार के साथ मिलकर किए जाते हैं। भले ही कस्टमर म्यूज़िक परफ़ॉर्मेंस (या स्टैंड-अप एक्ट या नाटक, जैसा भी हो) देखने के लिए टिकट के पैसे दे रहा हो, लेकिन बिज़नेस मॉडल का मकसद बिज़नेस के दूसरे हिस्से से होने वाले रेवेन्यू को बढ़ाना है। ऐसे में, मूवी देखने वाले थिएटर मालिकों द्वारा तय की गई एंट्री की शर्त मानने को मजबूर हैं, यानी मूवी हॉल के अंदर बाहर से खाने-पीने की चीज़ें ले जाने पर रोक।

33. हमने देखा कि बहस के दौरान, अपील करने वालों की तरफ से यह कहा गया कि मूवी देखने वालों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सिनेमा हॉल के अंदर बिना कोई चार्ज लिए साफ़ पीने के पानी की सप्लाई का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि जब कोई छोटा बच्चा या शिशु माता-पिता के साथ आता है, तो आम तौर पर सिनेमा हॉल मालिकों को शिशु या बच्चे की न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर ठीक-ठाक मात्रा में खाना या ड्रिंक्स ले जाने पर कोई एतराज़ नहीं होता है।

34. पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मूवी देखने वालों के लिए, जिन्हें शायद उनके डॉक्टरों ने खाने-पीने की सलाह दी हो या जो अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से खाने-पीने की चीज़ों पर रोक लगा रहे हों, हम सिनेमा हॉल मालिकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे ऐसे मूवी देखने वालों की रिक्वेस्ट पर केस-बाई-केस बेसिस पर ध्यान दें।

35. ऊपर दी गई स्थिति को देखते हुए, हम अपील मंज़ूर करते हैं और ऊपर बताए गए निर्देश (i) के संबंध में हाई कोर्ट के 18 जुलाई 2018 के विवादित फ़ैसले और आदेश

को रद्द करते हैं। हाई कोर्ट के बाकी निर्देश अपील का विषय नहीं हैं और इसलिए, इस फ़ैसले में उन पर विचार नहीं किया गया है।

डी. आखिरी टिप्पणी

36. खत्म करने से पहले, यह ध्यान देना ज़रूरी है कि 1975 के रूल्स का रूल 87 इस तरह है:

i. लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन नियमों के अंतर्गत लाइसेंस धारक राज्य के सभी सिनेमाघरों में टिकटों का बिक्री मूल्य एक समान हो।

ii. लाइसेंसिंग अथॉरिटी यह पक्का करेगी कि किसी भी ऑडिटोरियम में दूसरी बार दिखाई गई किसी भी पिक्चर के लिए लाइसेंस होल्डर कम रेट चार्ज करे।

37. रूल 87 की वैलिडिटी को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 8(iii) में रूल 87 के सब-क्लॉज (i) और (ii) के बारे में ये निर्देश जारी किए:

iii. जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ-साथ लाइसेंसिंग अथॉरिटी/राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे जम्मू-कश्मीर सिनेमा (रेगुलेशन) रूल्स, 1975 के रूल 87(i) और (ii) के मुताबिक राज्य के सभी सिनेमाघरों में टिकटों के बिक्री मूल्य के संबंध में एक जैसी कीमतें बनाए रखें।

38. हाई कोर्ट के ऊपर दिए गए निर्देश का यह मतलब नहीं निकाला जाएगा कि वह अभी के रुल 87 के अलावा कोई और ज़रूरत थोप रहा है।

39. अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन हैं, तो उन्हें निपटा दिया गया है।

<u>टी.सी (सी) संख्या - 28/2019 और 29/2019</u>

40. सिविल अपील नंबर 77/2023 में दिए गए फैसले को देखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट से टी.सी (सी) नंबर 28/2019 और बॉम्बे हाई कोर्ट से टी.सी (सी) नंबर 29/2019 में ट्रांसफर की गई रिट याचिका खारिज की जाती हैं। ट्रांसफर किए गए केस का निपटारा किया जाता है।

41. अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन हैं, तो उन्हें निपटा दिया गया है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।